नेपाल में नक्सलवादी हिंसा एवं भारतीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत विकल्प

बीज शब्द : नेपाल की स्वतंत्रता और अखण्डता, नेपाल में नक्सलवाद, भारत नेपाल की खुली सीमा, नक्सलवादी हिंसा, भारतीय सुरक्षा

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत नेपाल में अस्थिरता स्वाभाविक है। नेपाल की इस अस्थिरता का लाभ उठाकर विदेशी प्रेरित और समर्थित अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपने स्वार्थ साधना का शिकार बनाकर अबोध जनता का दुरुपयोग करती हैं। नक्सलवादी नेपाल में यही कर रहे हैं। इससे भारत नेपाल संबंध भी प्रभावित हो रहा है। यह शोध आलेख इस परिप्रेक्ष्य में नेपाल की राजनैतिक स्थितियों की विवेचना करता है और भारतीय सुरक्षा का नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करता है।

अश्विनी कुमार सिंह
एसोसिऐट प्रोफेसर,
अमरदीप सिंह चौहान
रक्षा एवं स्त्रेतजिक अध्ययन विभाग,
हे०न०ब०ग० केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
श्रीनगर,
गढ़वाल।

नेपाल प्रधानतया मध्य हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढालों पर स्थित है, जिसके उत्तर एवं पूर्व क्षेत्रफल 1,41,577 वर्ग किमी0 नेपाल पूर्व से पश्चिम 830 किमी0 लम्बाई तथा औसत 160 किमी0 चौड़ाई में फैला भारत का पड़ोसी स्वतंत्र एवं सार्वभौम देश हैं। इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत है। भारत उसका निकटतम पड़ोसी राष्ट्र है, इसकी भौगोलिक सीमायें एक दूसरे से मिली हुई हैं। जब से तिब्बत चीन के प्रत्यक्ष शासन में आया है, तब से नेपाल की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र रहा है और अपने वीर और पराक्रमी निवासियों के लिए विश्व-विश्रुत है। नेपाल भारत का एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ आपसी सुख-दुख, रिश्ते-नाते, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, आदि तमाम तरह की परस्पर निर्भरताएँ हैं। भारत-नेपाल के सांस्कृतिक, सामाजिक भावनात्मक और आर्थिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं और इन साझा सांस्कृतियों, रूढ़ियों एवं परम्पराओं को अलग किया भी नहीं जा सकता, किंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत और नेपाल के सम्बन्ध जैसे मधुर होने चाहिए, वैसे परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण नक्सलवाद एवं माओवाद है, नक्सलवाद मुख्य रूप से मार्क्सवाद के वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके तहत समाज के शोषित, उपेक्षित और दलित वर्ग अपनी संघर्ष शक्ति से पूँजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों एवं शासकों को अपना लक्ष्य बनाते हैं। यहाँ तक की आचार्य कौटिल्य ने भी कहा था कि राज्य का भूमि क्षेत्र इतना हो कि वह निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनकी शत्रुओं से रक्षा भी कर सके। आचार्य कौटिल्य का उपरोक्त वाक्य वर्तमान भारत, उसकी सामाजिक संरचना और दूसरे राज्यों के लिए स्वप्नद्रष्टा प्रतीत हो रही है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ होता तो स्थितियाँ कुछ और ही होती जबकि सच्चाई यह है कि अब विभिन्न आन्तरिक सुरक्षा समस्यायें उत्पन्न हो गयी है, जिसमें नक्सलवाद व माओवाद ने राज्यों में बहुत तेजी से पाँव फैलाना शुरू कर दिया है।

नेपाल का विश्वदृष्टिकोण अधिकांशत: उसके अपने दोनों बड़े पड़ोसियों भारत और चीन से सम्बन्धों की दशा और दिशा पर ही आधारित रहा है। विश्व में और कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, जिसमें जाति, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सम्बन्धों से दो देश आपस में इस तरह से बँधे हों। सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, राजनैतिक विकास, सामुदायिक जीवन पद्धति और मुस्लिम जनसंख्या की अधिकता से भारत-नेपाल सीमा का विशेष स्त्रेतजिक महत्व है। भारत-नेपाल सम्बन्ध 1950 की संधि

के आधार पर विकसित हुए हैं, लेकिन नेपाल में जनता द्वारा पंचायत व्यवस्था के खात्मे और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उग्र प्रदर्शन और आन्दोलन निरन्तर होतेह रहे हैं। भारत ने भी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया।

भारत-नेपाल के सम्बन्धों की खटास-मिठास, सटे पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण चलती ही रही, किन्तु नेपाल के महाराजा त्रिभुवन नारायण शाह के मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र महेन्द्र विक्रम शाह ने सत्ता सम्भाली तब से भारत-नेपाल में कुछ खटास परिलक्षित होने लगी। 1960 के दशक में टंका प्रसाद आचार्य जब नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल में नेपाल का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। आचार्य का अक्टूबर 1956 में चीन यात्रा के पश्चात् चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई जनवरी 1957 में नेपाल की राजकीय यात्रा पर आये। जहाँ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेपाल की स्वतंत्रता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए चीन, नेपाल की यथाशक्ति सहायता करेगा। निश्चय ही यह एक कूटनीतिक अभिभाषण था, जिसके विभिन्न अभिप्राय हो सकते थे। इस वक्तव्य के पश्चात् नेपाल और चीन के मध्य तिब्बत के सम्बन्ध में एक सन्धि हुई और चीन ने नेपाल को 6 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद भी की। इस दौरान नेपाली जनता में यह अधिक प्रचार किया गया कि नेपाल की स्वतन्त्रता को भारत से खतरा हो सकता है। भारत-नेपाल सम्बन्धों की यह स्थिति इसी प्रकार 1980 तक बनी रही। 19 अप्रैल 1990 को नेपाल में लोकतन्त्र की स्थापना हुई। सन् 1991 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मार्च 1994 में नेपाल में राजनीतिक संकट प्रारम्भ हो गया। वास्तविक रूप में कोइराला सरकार बनते ही नेपाल में माओवादियों के संगठन बने जिन्होंने राजशाही के खात्मे की बात की और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने नेपाल में आतंकवादी गतिविधियाँ फैलानी शुरू की। नेपाल में अभी राजशाही हत्याकाण्ड की आग ठण्डी भी नहीं हो पाई थी कि माओवादियों ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नेपाल के सम्बन्ध कथित तौर पर भारत के साथ सामान्य भले ही हों, किन्तु इसे सौहार्द्रपूर्ण और विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। नेपाल का चीन की ओर झुकाव, आई0एस0आई0 की बढ़ती गतिविधियाँ, भारत नेपाल वैचारिक विरोधाभास, नेपाली माओवादियों का भारत के नक्सलियों तथा चीन के साम्यवादियों से सम्बन्ध आदि ऐसे तथ्य हैं जो भारत और नेपाल सम्बन्धों में एक नये स्त्रेतजिक अध्याय का सृजन कर रहे हैं, जो भारत के सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील साबित हो सकते हैं।

सन् 2004 में माओवाद कम्युनिस्ट सेन्टर और पीपुल्स वार ग्रुप ने नया समूह सी0पी0आई0 (माओवाद) बनाया, जिनका मुख्य उद्देश्य फसलों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि सत्ता पर काबिज होना था। दोनों गुटों को एक जुट होने से यह आन्दोलन आज मजबूती के शिखर पर पहुँच गया है। इन गुटों की संयुक्त सेना का नाम पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी रखा गया है। इसके साथ 20 से अधिक और छोटे-बड़े नक्सली संगठन सक्रिय हैं। नक्सलियों ने खुद को आधुनिक गुरिल्ला सेना में तब्दील कर लिया है। वर्तमान में इनके लड़ाकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। माओवादी संगठन के एक नेता का कहना था कि भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवान, नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ-साथ नेपालियों का जम कर शोषण करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। वास्तविक रूप में तथाकथित नक्सल समस्या भारत की आन्तरिक सुरक्षा की सबसे गम्भीर समस्या होती जा रही है। सामान्यत: यह समझा जाता है कि जम्मू-कश्मीर की समस्या सबसे बड़ी है, परन्तु यदि भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से या समस्या पर विचार किया जाय तो नक्सल समस्या सबसे अधिक जटिल साबित हो रही हैं। इस बात का अनुमान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जा रही केन्द्रीय सहायता राशि को देखकर लगाया जा सकता है। जिसमें सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से निपटने में केन्द्रीय मदद के तौर पर करोड़ों रुपये दिये गये, वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों को इस समस्या के समाधान के लिए भी करोड़ों रूपये मुहैया कराये गये हैं। यह एक सुखद स्थिति है कि इस समय नेपाल एक लोकतांत्रिक देश के नये रूप में और अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। नयी व्यवस्था के अनुसार नेपाल अब हिन्दू राष्ट्र न होकर पंथनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है तथा वहाँ की राजशाही अब प्रतिनिधि मात्र बनकर रह गयी है। वस्तुत: भारत को नेपाल से लेकर जो कुछ भी परेशानी थी, चाहे वह नीतिगत हो या फिर माओवादी हिंसाजनित समस्या, सभी के मूल में राजशाही व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक नेताओं का समर्थन तो भारत को सदा से ही मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल में लोकतंत्र के प्रभावी होने से निश्चय ही भारत को राहत मिली होगी, किन्तु भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि 21वीं शताब्दी की तस्वीर 20वीं शताब्दी से काफी भिन्न है। उस समय भारत नेपाल के सन्निकट था, जबकि आज चीन उसका हमदम बन चुका है। अत: भारत को नेपाल नीति में नये कूटनीतिक दाँव-पेंच चलने होंगे, जिसका पहला कदम यही होगा कि वह नेपाल में लोकतंत्र का दिल खोल कर समर्थन करे।

ज्ञातव्य है कि जब से नेपाल में माओवादी आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई हैं, नेपाल से जुड़े सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों में एक

दहशत सी व्याप्त हो गयी है। चूँकि इन माओवादियों के निशाने पर भारतीय मूल के नेपाली लोग ज्यादा हैं और इनके सम्बन्ध सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के निवासियों से भी है। माओवादी प्रमुख प्रचंड द्वारा 31 दिसम्बर, 2005 को गत युद्ध विराम समाप्त करने की घोषणा तथा उसके तत्काल बाद नेपाल के मैदानी इलाकों में हुई हिंसा की वारदातों के बाद से नेपाल की तराई पट्टी में रहने वाले भारतीय मूल के नेपालियों में आतंक पैदा हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ देश के उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल ने 3-4 अगस्त, 2014 को नेपाल की यात्रा की। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश हाइड्रो पावर, कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण, पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा संस्कृति व खेलों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के सिलसिले में 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात् किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल की यह यात्रा थी।

नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ सम्पन्न वार्ता में 1950 की भारत-नेपाल मैत्री सन्धि तथा उसके पश्चात् सम्पन्न विभिन्न समझौतों की समीक्षा के लिए सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों में हुई 23 वर्ष के अंतराल के पश्चात् भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की काठमांडू में 26 जुलाई, 2014 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रति दोनों प्रधानमंत्रियों ने सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच विद्यमान सीमा विवाद को भी शीघ्र ही पूरी तरह निपटाने की आवश्यकता को दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया। द्विपक्षीय वार्ता में नेपाल की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि नेपाली भूमि का किसी भी तरह से भारतीय हितों के विरुद्ध उपयोग नहीं होने दिया जाएगा।

भारतीय प्रधानमंत्री के काठमांडू प्रवास के दौरान नेपाल के जिन अन्य प्रमुख नेताओं ने उनसे भेंट की उनमें माओवादी नेता प्रचंड भी शामिल थे इन नेताओं के साथ बातचीत में श्री मोदी ने उनसे दल के हित में नहीं, बल्कि देश के हित में सोचने का आह्वान किया। दो दिन की अपनी इस नेपाल यात्रा के प्रति पूर्ण संतोष प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया, नई दिल्ली वापस लौटकर उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान नेपाल में जिससे भी वह मिले, उसके मन में राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक समृद्धि की ललक उन्होंने देखी है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संसाधनों, प्रतिभा और विविधता से परिपूर्ण नेपाल शीघ्र ही एक मजबूत समग्र और समृद्ध देश के रूप में अपने आपको स्थापित कर लेगा।

वास्तविक रूप में भारत नेपाल की खुली सीमा, भारत में तस्करी का सुगम मार्ग है। चूंकि खुली सीमा होने के नाते यहाँ पर्याप्त चौकसी की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसका लाभ तस्कर अक्सर उठाते रहते हैं। तस्करी के इन सामानों में विस्फोटक पदार्थ, हथियार, जाली नोट, मादक पदार्थ आदि शामिल होते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई0एस0आई0 सहित अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों की भारत-नेपाल सीमा पर सक्रियता अब देश के समक्ष चुनौती बनती जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मुड़िला घाट, कोल्हुई थाना क्षेत्र का खैराघाट, भगवानपुर, श्यामकाट, फरेन्दा तिवारी, केवटलिया, खनुआ हरदी डाली, शेख फरेन्दा, झुलनीपुर, लक्ष्मीपुर, बरगदवा अशोकवा, ठूठीबारी, मरजादपुर, खैरहवा दूबे, अहिरौली, श्योतरा, सहित एक दर्जन से ज्यादा स्थान हैं जहाँ से खुले आम खाद, सीमेन्ट व खाद्यान्न सहित तमाम भारतीय सामान नेपाल भेजे जाते हैं। इस धंधे में दो सौ से ज्यादा कैरियर लगे हुये हैं। यह उनकी रोजी-रोटी का साधन है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सुरक्षा सन्दर्भों में भारत के समक्ष नेपाल की ओर से चाहे अनचाहे कई प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। इनमें से सीमाओं का सिकुड़ता स्वरूप, सीमा-अतिक्रमण अपराधियों व तस्करों को संरक्षण, आई0एस0आई0 का बढ़ता नेटवर्क, माओवादी हिंसा की काली छाया व बृहत्तर नेपाल बनाने की घोषणा, मादक पदार्थो की तस्करी, देह-व्यापार, जाली नोटों का कारोबार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऐसी स्थिति में भारत को अपने सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर और भी दृढ़ता से अमल करना होगा तथा नये आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। मेरी समझ से निम्न तथ्यों को अमल में लाया जाय, तो भारत की नेपाल की ओर से होने वाली सुरक्षा सम्बन्धी चिंताएँ काफी हद तक दूर हो सकती हैं।-

01. यह सम्भावना कि उत्तरी सीमाओं से नेपाल में घुस आई कोई शक्ति (चीन) भारत की मुख्य भूमि तक आसानी से पहुँच सकती है, क्योंकि भारत-नेपाल सीमाएँ किसी प्राकृतिक अवरोध से विभाजित नहीं है। अत: इसकी बाड़बन्दी करके इसकी पूर्ण चौकसी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

02. आवागमन एवं व्यापार का कार्य सीमित चौकियों के माध्यम से हो, ताकि यहाँ से गुजरने वालों की सघन जाँच की जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से यह परम आवश्यक है।

03. नेपाल ऐसी आंतरिक और विदेश नीति अपना सकता है, जो भारत के सुरक्षा हितों के लिए घातक हो।

04. भारत-नेपाल दोनो देशों के नागरिकों के आवागमन के निमित्त परिचय-पत्र अथवा परमिट की प्रणाली लागू की जाए। तस्करों एवं अवैध व अवांछित लोगों के आवागमन पर रोकथाम लगायी जा सके।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश से नेपाल भी अछूता नहीं है। जिस प्रकार सम्बन्धों, आवश्यकताओं, व्यवहार, संस्कृति आदि का

शेष पृष्ठ 90 पर

बहुत श्रेष्ठ रहा है, उस चिन्तन को समझें तथा आगे बढ़ाएं।

डॉ0 मनोज पटैरिया अतिरिक्त महानिदेशक प्रसार भारती ने कहा कि नयी पीढ़ी जिस तेजी व जुझारूपन से हिन्दी के प्रचार प्रसार को अपना रही है वह प्रसन्नता की बात है। हिन्दी में विज्ञान बहुत आगे जा रहा है तथा और भी आगे जायेगा। बाजारवाद के प्रभाव के चलते कौन से विज्ञान का संचार करें। फसल, स्वास्थ्य नुकसान या कम्पनी जिसे प्रसारित करना चाहती है? ये विचारणीय बिन्दु हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ0 अखिलेश पाण्डेय ने विद्यालयी बच्चों से विज्ञान का प्रचार-प्रसार करने की अपील की तथा कहा कि उनके सहयोग से विज्ञान आगे तक जा सकता है। अनुसंधान यदि अच्छा है तो भाषा की कोई बाधा नहीं आएगी। अंग्रेजी के कारण बच्चों का ड्रापआउट होना शर्म की बात है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा में विज्ञान को कैसे समझें। इसका प्रचार प्रसार कैसे करें। जनसामान्य तक उसे कैसे पहुँचाएं। हिन्दी को प्रोत्साहित करना होगा तथा नवाचार के निम्न स्तर को उँचा उठाना होगा, स्कूल से लोगों में भाषा के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना होगा। हम विकास की बात विज्ञान के साथ करें तभी समाज का उचित विकास व कल्याण सम्भव है। प्रतिभागीगण अपने ज्ञान व अनुभव का लाभ लोगों तक पहुचाएं। अच्छी पाठ्य-सामग्री व पुस्तकें उपलब्ध कराएं। साथ ही, पत्रकारिता के गिरते स्तर को उँचा उठाना होगा।

भारत के प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से मीटिंग के दौरान अधिक से अधिक हिन्दी में बात करने की अपील की जो कि राष्ट्र एवं राष्ट्र भाषा के लिए गर्व की बात है। हमें अपने ही राष्ट्र में अपनी भाषा की स्थापना करनी पड़ रही है जिसके उत्तरदायी हम और आप नहीं हैं। कारण एक हजार वर्ष की गुलामी है। हमने ऐसी जाति की गुलामी की है जिसने अंग्रेजी और अंग्रेजियत हमारे मन और मस्तिष्क में डाल दी। व्यवहार व सोच में अंग्रेजी आ सकती है पर खून में नहीं। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि अंग्रेजी रहे न रहे पर हिन्दी स्थापित होनी चाहिए। इस विषय में सोचने पर पता चलता है कि सभी भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत है और स्थानीय परिस्थितियों के कारण यह प्रचलन से दूर होती चली गयी। बाइनरी सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत ही है। हम मोहपाश में फँसे हैं तथा एक ऐसी भाषा को बोलन-लिखने-सोचने में लगे हैं जो हमारी भाषा है ही नहीं। सहज प्रभावी सम्प्रेषण के लिए मातृभाषा ही उत्तम है। अगर हम ऐसी भाषा को अपने से चिपकाएंगे तो हम अवैज्ञानिक कहलाएंगे। ये हमारी दासता का हैंगओवर है। इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा।

उत्तराखण्ड से पधारे प्रतिभागी अशोक दुबे ने कहा कि सम्मेलन से अच्छे विचार उभर कर सामने आए हैं जिनसे मैं शत-प्रतिशत सहमत हूँ, परन्तु हम रास्ता जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। हिन्दी की स्थापना हेतु व्याख्यान तथा व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हुए राष्ट्रीय गौरव की भावना से कार्य करना होगा।

◆◆◆

पृष्ठ 71 का शेष

भूमण्डलीकरण हो रहा है और राष्ट्रों के व्यक्तिगत मामले भी अन्तर्राष्ट्रीय होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल जैसे लघु एवं निर्धन राष्ट्र का वैश्विक वातावरण से प्रभावित होना स्वाभाविक है। चूँकि नेपाल भारतीय खुली भू-सीमाओं से तीन ओर से संलगन है। अत: 21वीं शताब्दी के बदलते परिवेश से प्रभावित हो रहे नेपाल का स्त्रातेजिक महत्व भारत के लिए और भी बढ़ जाता है। नेपाल देश, किसी भी ऐसे राष्ट्र से सहायता प्राप्त कर सकता है, जो उसे हितकर प्रतीत हो। बाद में भले ही यह सौदा उसके लिए नुकसानदायक क्यों न हो।

सन्दर्भ:-

1. डॉ0 बी0 पी0 राव, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, संस्करण 2010 पृ0सं0 143
2. शेखर अधिकारी, आधुनिक स्त्रातजिक चिन्तक, पृष्ठ सं0 376
3. डॉ0 एम0 डी0 धर्मदानी, इण्डो नेपालीज रिलेशन्स, 1997 पृ0सं0 10
4. कम्पलसंस ऑफ ए लैण्ड लास्ड स्टेट, ए स्टडी ऑफ नेपाल-इण्डियन रिलेशन, इंदु बाला
5. दी किंगडम ऑफ नेपाल, जे0 के0 चोपड़ा
6. हिन्दुस्तान, 17 फरवरी 2011
7. इण्डियन डिफेन्स ईयर बुक, आर0 के0 जसवीर सिंह
8. अमर उजाला, वार्षिकी 2015, पृ0सं0 129
9. दैनिक जागरण 23 मार्च, 2007
10. सहारा समय, 14 मई, 2005

◆◆◆